लाख उत्पादन की उन्नती में लाख उद्योग की भूमिका

गजानन अग्रवाल

सेन्टल इंडिया लाख डेवलपमेंट सोसायटी, गोंदिया, महाराष्ट्रा

मैं भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान को लाख के उत्पादन से जुड़े सामयिक मुद्दों पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए बघाई एवं धन्यवाद देता हूँ। उपरोक्त विषय पर चर्चा हेतू मैं संस्थान का आभार वयक्त करता हूँ । भारतवर्ष लाख उत्पादन में पहले सबसे अग्रणीय रहा किन्तु कुछ विगत् कुछ वर्षो से निरत्तर लाख की खेती कम होती गयी और 2009 से इसकी खेती तकरीबन 5 प्रतिशत पर आ गयी, यह एक चिंता का विषय है ।

लाख तथा लाख से उत्पादित पदार्थो के भाव हमेशा फसल तथा मार्केट डिमांड पर अवलम्बित होने से कम-ज्यादा होते रहे हैं । अनुसंधान केन्द्र ने विगत् 8-10 वर्षो से महाराष्ट्र में भी गोंदिया की संस्था सेन्ट्रल इंडिया लेक डेवलपमेंट सोसायटी के साथ काफी सहयोग दिया, जिससे महाराष्ट्र का उत्पादन जो कि 1 प्रतिशत था बढ़कर तकरीबन 4 प्रतिशत तक हो गया था । उसी प्रकार मघ्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लाख का उत्पादन विगत् वर्षो में बढ़ा था । अनुसंधान केन्द्र ने गुजरात, आन्ध्रप्रदेश राज्यों में भी लाख उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कार्य भी किया किन्तु राज्यों में गलत प्रणालियों के कारण कास्तकार बंधु, आदिवासी का रुझान लाख की खेती करने में कम रहा । उदाहरण के तौर पर गुजरात राज्य में लाख पर वैट टैक्स का होना, जिससे वहाँ के कास्तकार तथा व्यापारीगण वैट टैक्स की प्रणाली होने से लाख उत्पादन में दिलचस्पी कम रखते हैं ।

मध्यप्रेदश शासन द्वारा सितंबर 2009 से लाख के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जबकि लाख 95 प्रतिशत कास्तकार तथा आदिवासी बंधु अपनी स्वयं की खेती तथा पडीत जमीन के पेड़ों से उत्पादन लेते हैं । मध्यप्रदेश शासन ने 2003 में इस लघु वनउपाज को पूरी तरह से आवाजाही से मुक्त कर दिया उसके पश्चात 2003 के बाद मध्यप्रदेश के लाख का उत्पादन जो कि संपूर्ण भारत का 5 प्रतिशत हिस्सा था, वह बढ़कर 9 प्रतिशत हो गया।

छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख उत्पादन हेतु काफी प्रयास किये, जो कि सराहनीय है । वन विभाग द्वारा वन कर्मचारियों को तथा आदिवासी व कास्तकार बंधुओं को भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, राँची से प्रशिक्षण दिलवाया गया साथ ही लाख उत्पादन हेतु लाख बिजाई का भी वितरण किया गया । इसके अलावा लाख से चौरी बनाने हेतु कुछ मशीनें भी बजट सत्र में आदिवासी प्रकल्प को उपलब्ध कराया जिसमें छत्तीसगढ़ ने काफी आर्थिक योगदान लाख उत्पादित क्षेत्रों को दिया । आन्ध्रप्रदेश में कच्ची लाख पर आवाजाही के रोकटाक के कारण उत्पादित लाख का गैरकानूनी ढंग से

आवाजाही होती है, जिससे लाख उत्पादन को सही कीमत नहीं मिलती और इस कारण किसान लाख उत्पादन करने का इच्छुक नहीं रहता ।

महाराष्ट्र में भी इस वर्ष लाख उत्पादित जिलों - गोंदिया, भंडारा, गड़चिरोली, अमरावती, सवतमाल, चंद्रपुर इत्यादि में वन विभाग द्वारा आदिवासियों के उत्थान हेतु 2 करोड़ से ज्यादा की राशि का आर्थिक योगदान दिया किन्तु लाख उत्पादन की संपूर्ण जानकारी नहीं होने से उसका उत्पादन हेतु सही उपयोग नहीं हो पाता जबकि अनुसंधान संस्थान अपने वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण हेतु संपूर्ण भारत में भेजने के लिये तत्पर रहता है फिर भी इन राज्यों द्वारा अनुसंधान संस्थान से मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण नहीं लिया जाता है, यह दु:ख का विषय है ।

झारखंड जिसका कि भारत में लाख उत्पादन में सबसे अधिक योगदान रहा किन्तु कुछ वर्षो से यहाँ का उत्पादन काफी प्रभावित हुआ जबकि लाख से चपड़ा इत्यादि बनाने के कारखाने झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में ही अत्याधिक है । यह एक चिंतन का विषय है कि भारतवर्ष जो अग्रिम था, उससे अधिक का उत्पादन थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम इत्यादि राष्ट्रों में होने लगा । लाख हमारी धरोहर है तथा पलास, बेर, कुसुम इत्यादि वृक्षों के पेड़ भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में है जिससे लाख की खेती करके हमारे कास्तकार बंधुओं, आदिवासी, दुर्बल घटक को आर्थिक योगदान प्राप्त हो सकता है, जिससे आर्थिक परिस्थितियों में सुधार होगा तथा इस लाख के उत्पादन से चपड़ा इत्यादि निर्मित करके हम उसका अधिकाधिक निर्यात कर सकते हैं जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी । भारतवर्ष में जनसंख्या को देखते हुये काफी नवयुवक बेरोजगार हैं जिन्हें की इस लाख उत्पादन से कमाई का स्रोत प्राप्त हो सकता है । साधारण बात है कि जिस पेड़ के दोहन से हमें आर्थिक लाभ होगा उसका संरक्षण निश्चित रुप से होगा जिससे पर्यावरण की रक्षा होगी, पेड़ नहीं कटेंगें तथा नये पेड़ लगाने की जागरुकता हर व्यक्ति में आयेगी । उपरोक्त संबोधन का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष के उन राज्यों में जहां कर लगाने का प्रावधान किया गया है उन राज्यों में इस लाख तथा लाख से उत्पादित पदार्थो पर किसी प्रकार का वन विभाग द्वारा आवाजाही पर रोक तथा किसी प्रकार का भी टैक्स कृषि मंडी सेस इत्यादि नहीं होना चाहिये । मध्यप्रदेश शासन ने भी जो लाख पर राष्ट्रीयकरण किया है, उस कारण वहाँ का उत्पादन 9 प्रतिशत से घटकर 0.1 प्रतिशत हो गया अत: मध्यप्रदेश शासन से निवेदन है कि वे लाख पर से राष्ट्रीयकरण हटा कर पूर्ववत लाख की खेती तथा आवाजाही को मुक्त कर दें । स्वाभाविक है कि वे किसी भी कार्य को कुछ लोगों द्वारा करने के बजाय हजारों तथा लाखों लोग करें, तो निश्चित रुप से उसका उत्पादन बढ़ेगा तथा स्वयं के माल की रक्षा हर व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ के निहित ज्यादा करता है तथा कास्तकार बंधु अपना उत्पादित लाख मंडियों में लाकर ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचने का प्रयास करता है ।

आज की परिस्थितियों में लाख उत्पादित करनेवाले कास्तकार व आदिवासी बंधु मजबूरन औने-पौने दामों में गाँव के छोटे व्यापारियों को अपना उत्पादित पदार्थ बेचने के लिये बाध्य होते हैं तथा वे

व्यापारीगण किसी तरह भी लाख की आवाजाही कर लेते है जिससे लाख उत्पादक को उचित मूल्य नहीं मिल पाता जिससे उसकी लाख उत्पादन में इच्छा कम होती जा रही है ।

मैं, कास्तकार बंधुओं से भी यह अपेक्षा करता हूँ कि वे लाख की खेती अनुसंधान केन्द्र द्वारा दर्शित नियमों से करें जिससे उन्हें प्रति पेड़ ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा, पेड़ों से लाख की टहनियाँ काटने के पश्चात उसे सही ढंग से खेत या जंगल से लाख छिलने की जगह तक लायें जिससे की रास्ते में सूखी हुयी लाख सड़क पर ना गिरे तथा लाख लकड़ियों से निकालते समय फर्श पर या प्लास्टिक इत्यादि बिछाकर निकालें, अन्यथा लाख में मिट्टी व रेती इत्यादि का समिश्रण हो जाता है जिससे लाख की क्वालिटी खराब होती है । लाख के बड़े व्यापारी, अड़तिया, कारखानेदारों का भी कर्त्तव्य होता है कि वे लाख उत्पादन के लिये कास्तकार बंधुओं को प्रोत्साहित करें, समय-समय पर अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयेाजन करें तथा इस व्यवसाय में होने के कारण इसमें आर्थिक व शारीरिक योगदान भी करें । वन विभाग के अधिकारिगण भी लाख उत्पादन में पूर्ण सहयोग करें जिससे उनके वनविभाग से लगे हुये ग्रामों का उत्थान भी होगा तथा पेड़ों की रक्षा भी होगी। वन विभाग को या किसी भी राज्य को खरीदी-बिक्री के कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिये क्योंकि लाख की खेती में लाख के पेड़ों की टहनियों की छंटाई, लाख वीहन बांधना, पेड़ों से कुछ प्रतिशत कच्ची लाख काटना, बाद में फूंकी लाख काटना बिजाई हेतु कुछ पेड़ों को अगली फसल हेतु रखना यह सब प्रक्रिया कास्तकार बंधु तथा लाख उत्पादित व्यक्ति ही निश्चित रुप से कर सकता है । वन विभाग तथा राज्य शासन लाख उत्पादित कास्तकार, अदिवासी बंधु को प्रशिक्षण देना, लाख बिजाई हेतु थैलियाँ, उपकरण, कीटनाशक दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध कराना, राज्य के हर लाख उत्पादित जिलों में वन विभाग द्वारा लाख बीजागुणक केन्द्र का निमार्ण करना चाहिये जिससे लाख उत्पादित बंधुओं को रियायती दर में लाख के बीज प्राप्त हो सके तथा उसी लाख बीजागुणक केन्द्र में लाख प्रशिक्षण का शिविर आयोजित कर उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य वन कार्य वन विभाग के माध्यम से किया जाना चाहिये ।

उपरोक्त बातों में राज्य के कृषि अनुसंधान केन्द्र को भी सहयोग करना चाहिये ।भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और उपरोक्त बातों पर हम विचार करें तो निश्चित रुप से हम लाख का उत्पादन बढ़ा सकते हैं तथा हमारे गामीण बंधुओं को आर्थिक स्तर में भी सुधार कर सकते हैं ।

वर्ष 2009 से लाख का उत्पादन एकदम कम होने का कारण मानसून का विलंब से आना तथा कम बारिस होने से लाख के कीड़ें अधिकाशत: मर गये किन्तु जहाँ नदी, तालाब इत्यादि में पेड़ थे वहाँ पेड़ों में हरियाली होने के कारण कुछ लाख पोषक पेड़ तथा कीड़े जीवित रहे । अब हमें उत्पादन बड़ाने हेतु कम से कम तीन वर्ष लगेंगें, जिसमें सभी का सहयोग यानिकी भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, वन विभाग, लाख व्यावसायी, कारखानेदार, राज्य के कृषि विभाग, केन्द्र शासन द्वारा योगदान मिलने पर ही यह कार्य हो सकता है ।

उपरोक्त बातों पर विचार करके भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, राँची, केन्द्र शासन, लाख उत्पादित राज्यों के कृषि विभाग, वन विभाग को अपने विचार भेजें जिससे जिला परिषद पंयायत समितियों द्वारा इसका प्रचार-प्रसार तथा लाख की खेती को प्रोत्साहित किया जा सके। मध्यप्रदेश शासन इन परिस्थियों में अगामी अक्टूबर 2010 से लाख पर राष्ट्रीयकरण हटा लेंगें, ऐसी उम्मीद रखते हैं ।